

भारत सरकार  
विधि और न्याय मंत्रालय  
विधि कार्य विभाग  
लोक सभा  
अतारांकित प्रश्न सं 3431  
जिसका उत्तर शुक्रवार, 17 दिसम्बर, 2021 को दिया जाना है

### बंदी प्रत्यक्षीकरण वाद

**3431. श्री जगदम्बिका पाल :**

क्या **विधि और न्याय मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तारीख में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कितने बंदी प्रत्यक्षीकरण वाद लंबित पड़े हुए हैं ;

(ख) क्या लंबित पड़े बंदी प्रत्यक्षीकरण वादों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में बढ़ गई है ;

(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या है ;

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विधिविरुद्ध गतिविधि (निवारक) अधिनियम (यूएपीए) के अंतर्गत दर्ज मामलों और यूएपीए अभियुक्तों द्वारा दायर किए गए वादों और निरस्त किए गए ऐसे वादों तथा आज की तारीख तक लंबित ऐसे वादों की राज्य-वार संख्या क्या है ; और

(ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान यूएपीए के अंतर्गत दोषसिद्ध व्यक्तियों की राज्य-वार संख्या क्या है ?

### उत्तर

**विधि और न्याय मंत्री**  
( श्री किरेन रीजीजू )

**(क) से (ग) :** माननीय उच्चतम न्यायालय और आठ उच्च न्यायालयों के लिए उपलब्ध वर्तमान में जानकारी के अनुसार, लंबित बंदी प्रत्यक्षीकरण वाद की संख्या **उपाबंध-1** पर दी गई है ।

**(घ) और (ङ) :** राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय द्वारा विशिष्ट जानकारी नहीं रखी जाती है । तथापि, वर्ष 2018-2020 के अधीन विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निषेध) अधिनियम राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार रजिस्ट्रीकृत मामला (सीआर), चार्जशीट किया गया मामला (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीओएन), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), चार्जशीट किए गए व्यक्ति (पीसीएस) तथा दोषसिद्ध किए गए व्यक्ति (पीसीवी) **उपाबंध-2** पर दी गई है । नवीनतम प्रकाशित आंकड़ा वर्ष 2020 से संबंधित है ।

\*\*\*\*\*

क्रम सं.	न्यायालय का नाम	(क) आज की तारीख में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में कितने बंदी प्रत्यक्षीकरण वाद लंबित पड़े हुए हैं ;	ख) क्या लंबित पड़े लंबित बंदी प्रत्यक्षीकरण वादों की संख्या पिछले कुछ वर्षों में बढ़ गई है;	(ग) यदि हां, तो इसके कारण क्या हैं;			
1.	माननीय उच्चतम न्यायालय	मांगी गई जानकारी का रखरखाव नहीं किया जाता है। तथापि, उच्चतम न्यायालय विषय श्रेणी कोड 1300 के अनुसार लंबित मामलों की संख्या, जो पिछले चार वर्षों से भारत के उच्चतम न्यायालय में 'बंदी प्रत्यक्षीकरण मामलों' से संबंधित है, जैसा कि एकीकृत मामला प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईसीएमआईएस) से पुनः प्राप्त किया गया, 13.12.2021 को निम्नानुसार है:	लंबित मामलों की संख्या (वर्ष के अंत में)				
		वर्ष					
		2018	43				
		2019	40				
		2020	53				
		2021 (13.12.2021 के अनुसार)	52				
2.	माननीय बाम्बे उच्च न्यायालय	14.12.2021=108 को लंबित बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामले	वर्ष	लंबित मामले	बढ़ाए गए/घटाए गए		
			2018	12	10		
			2019	12	0		
			2020	5	-7		
3.	माननीय गुवाहाटी उच्च न्यायालय	09.12.2021=35 तक बंदी प्रत्यक्षीकरण के लंबित मामलों की संख्या	वर्ष	प्रारंभ में लंबित मामले	संस्थित मामले	निपटान किए गए मामले	अंत में लंबित मामले
			2018	11	11	6	16
			2019	16	24	20	20
			2020	20	17	8	29
			2021	29	24	18	35
4.	माननीय केरल उच्च न्यायालय	10.12.2021 को बंदी प्रत्यक्षीकरण के 24 मामले लंबित हैं ।	पिछले पांच वर्षों के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका में लंबित मामले नीचे प्रस्तुत किए गए हैं				
			30.11.2017 को			53	
			30.11.2018 को			38	
			30.11.2019 को			32	
			30.11.2020 को			79	
			30.11.2021 को			24	
5.	माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय	01.12.2021 को बंदी प्रत्यक्षीकरण के 97 मामले लंबित हैं ।	पिछले पांच वर्षों में बंदी प्रत्यक्षीकरण के लंबित मामलों के ब्यौरे :		लंबित मामलों के कारण :		
			31.12.2017	75	मामलों का भारी मात्रा में संस्थित होना तथा माननीय न्यायाधीशों के रिक्त पद बंदी प्रत्यक्षीकरण के मामलों के साथ सभी मामलों के लंबित होने के कारण हैं ।		
			31.12.2018	72			
			31.12.2019	76			
			31.12.2020	112			
			30.12.2021	97			
6.	माननीय मेघालय उच्च न्यायालय	शून्य	नहीं		प्रश्न ही नहीं उठता		

7.	माननीय पटना उच्च न्यायालय	बंदी प्रत्यक्षीकरण के लंबित मामलों की संख्या (फाइल किए गए वर्ष के अनुसार)		बंदी प्रत्यक्षीकरण के लंबित मामलों की संख्या (वर्ष के अंत में)	
		2019	1	2019	44
	2020	8	2020	29	
	2021	12	2021	46	
	10.12.2021 को कुल लंबित मामलों की संख्या	21	10.12.2021 को कुल लंबित मामलों की संख्या	21	
8.	माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय	कम्प्यूटर रिकार्ड के अनुसार तारीख 30.11.2021 को कुल 369 बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिकाएं लंबित हैं।	हां, पिछले पांच वर्षों के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण के लंबित मामलों की संख्या निम्न है :		
			वर्ष	लंबित मामलों की संख्या	
			2018	181	
			2019	243	
	2020	412			
9.	माननीय उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय	31.12.2021 को बंदी प्रत्यक्षीकरण के 41 लंबित मामले हैं।	नहीं	लागू नहीं होता	

उपाबंध-2

वर्ष 2018-2020 के अधीन विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम राज्य/संघ राज्यक्षेत्र वार रजिस्ट्रीकृत मामला (सीआर), चार्जशीट किया गया मामला (सीएस), दोषसिद्ध मामले (सीओएन), गिरफ्तार किए गए व्यक्ति (पीएआर), चार्जशीट किए गए व्यक्ति (पीसीएस) तथा दोषसिद्ध किए गए व्यक्ति (पीसीवी)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य	2018						2019						2020					
		सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पी वी सी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीवीसी	सीआर	सीसीएस	सीओएन	पीएआर	पीसीएस	पीवीसी
1	आंध्र प्रदेश	1	5	0	8	5	0	4	0	0	5	0	0	1	1	0	4	1	0
2	अरुणाचल प्रदेश	6	4	0	10	8	0	25	5	0	40	5	0	3	1	0	3	1	0
3	असम	308	65	0	170	71	0	87	30	0	112	35	0	76	21	0	49	29	0
4	बिहार	34	17	0	59	33	0	12	18	0	35	29	0	30	49	0	39	65	0
5	छत्तीसगढ़	10	2	0	4	4	0	2	7	0	32	32	0	3	2	0	27	20	0
6	गोवा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	गुजरात	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
8	हरियाणा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0
9	हिमाचल प्रदेश	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	झारखंड	137	45	20	97	81	21	105	109	16	202	143	17	86	36	3	69	60	3
11	कर्नाटक	1	0	0	0	0	0	7	4	0	6	14	0	1	2	0	2	2	0
12	केरल	17	1	0	6	1	0	53	4	0	25	8	0	18	5	0	24	42	0
13	मध्य प्रदेश	6	4	0	13	13	0	2	2	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0
14	महाराष्ट्र	1	1	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	7	7	0
15	मणिपुर	289	4	0	332	6	0	306	11	0	386	11	0	169	1	0	225	1	0
16	मेघालय	2	0	0	6	0	0	0	1	0	0	1	0	10	0	0	2	0	0
17	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	नागालैंड	8	2	1	10	2	1	9	2	0	18	3	0	2	3	0	7	5	0
19	ओडिशा	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0	0	1	0	0	1	0
20	पंजाब	6	3	0	27	22	0	3	5	0	30	27	0	19	8	0	44	41	0
21	राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	तमिलनाडु	2	1	0	15	3	0	270	103	0	308	130	0	3	82	16	92	94	21
24	तेलंगाना	0	0	0	0	0	0	1	1	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0
25	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	2	0	0
26	उत्तर प्रदेश	107	123	12	479	479	12	81	98	17	498	498	17	72	76	7	361	361	54
27	उत्तराखंड	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	पश्चिमी बंगाल	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	5	0	0
	<b>कुल राज्य</b>	<b>935</b>	<b>280</b>	<b>33</b>	<b>1236</b>	<b>736</b>	<b>34</b>	<b>969</b>	<b>401</b>	<b>33</b>	<b>1712</b>	<b>943</b>	<b>34</b>	<b>503</b>	<b>290</b>	<b>26</b>	<b>963</b>	<b>731</b>	<b>78</b>
29	अंदमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

31	दादर और नागर हवेली और दमन और दीव+	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	दिल्ली	2	5	1	8	7	1	2	4	0	9	6	0	6	3	0	12	6	0
33	जम्मू और कश्मीर*	245	32	0	177	110	0	255	78	0	227	190	0	287	105	1	346	271	2
34	लद्दाख	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल स.राज्य (एस)	247	37	1	185	117	1	257	82	0	236	196	0	293	108	1	358	277	2
	कुल(पूण भारत )	1182	317	34	1421	853	35	1226	483	33	1948	1139	34	796	398	27	1321	1008	80

स्रोत: भारत में अपराध

टिप्पण : '+' 018 और 2019 के लिए पूर्ववर्ती दादर और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र और दमन और दीव संघ राज्यक्षेत्र का संयुक्त डाटा

\*' 018 और 2019 के लिए लद्दाख सहित तत्कालीन जम्मू और कश्मीर राज्य का डाटा

\*\*\*\*\*